

प्रेषक,

ओम प्रकाश,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक  
प्रशिक्षण विभाग,  
हल्द्वानी (नैनीताल)।

**प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग-2**

देहरादून, दिनांक : 11 अप्रैल 2017

**विषय:-** प्रशिक्षण विभाग हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 हेतु लेखानुदान के माध्यम से आय-व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 312/XXVII(1)/2017, दिनांक 31 मार्च, 2017 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्यय में प्रशिक्षण विभाग के अनुदान संख्या-16 के अधीन वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों में संलग्न परिशिष्ट में उल्लिखित विवरणानुसार ₹452917/-हजार(रुपया पैंतालिस करोड़ उन्तीस लाख सत्रह हजार मात्र) की अधोउल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुये व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 1- वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों के अन्तर्गत उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय किशतों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि का कदापि व्यय नहीं किय जायेगा।
- 2- अधिष्ठान संबंधी अन्य अवचनबद्ध मदों की आय-व्यय के अन्तर्गत स्वीकृत बजट प्राविधान की धनराशि भी संबंधित प्रशासनिक विभाग/बजट नियंत्रक अधिकारियों द्वारा आहरण-वितरण अधिकारियों को इस प्रतिबंध के साथ उपलब्ध करा दी जायेगी कि इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि की कदापि व्यय नहीं की जायेगी एवं न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा।
- 3- किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1(वित्तीय अधिकारी प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 4- यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 5- अनुदानों को विभागवार एवं विभागाध्यक्षवार तैयार करने के कारण एक ही लेखाशीर्षक अनेक अनुदानों के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है, जिसके फलस्वरूप महालेखाकार के कार्यालय में व्यय को सही लेखाशीर्षक/अनुदान के अन्तर्गत पुस्तांकित करने में कठिनाई होती है...

और सुसंगत लेखाशीर्षक/अनुदान के अधीन त्रुटि रह जाने की सम्भावना बनी रहती है। इस हेतु आवश्यक है कि सभी वित्तीय स्वीकृतियों शासनादेश संख्या बी-2-2337/97 दिनांक 21 नवम्बर, 1997 के प्रारूप में सही लेखाशीर्षक इंगित करते हुये ही निर्गत की जाय, जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्य किया जाये।

- 6- विभाग में स्वीकृतियों एवं उसके सापेक्ष व्यय का रजिस्टर रखा जाय एवं प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय सम्बन्धी सूचना शासनादेशों की प्रतियां सहित वित्त एवं नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।
- 7- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल चालू स्वीकृति योजनाओं पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों के कार्यान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तहत ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 8- उपनल के कार्मिकों को मानदेय/वेतन का भुगतान मानक मद-16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान से किया जाता है। इस संबंध में निदेशक प्रशिक्षण को निर्देशित किया जाय कि इस मद में प्राविधानित/स्वीकृत धनराशि से उपनल के कार्मिकों का वेतन आहरित कर व्यय किया जायेगा। अन्य किसी प्रकार की देयता वेतन से इतर इस मद में व्यय हेतु उत्पन्न होती है तो शासन की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।
- 9- आयोजनागत पक्ष में स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2230-श्रम तथा रोजगार के अधीन **संलग्नक परिशिष्ट-"क"** में उल्लिखित सम्बन्धित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।
- 11- जिन मदों में वित्तीय वर्ष 2017-18 में लेखानुदान के माध्यम से स्वीकृत बजट के सापेक्ष धनराशि निर्गत नहीं की गयी है, उन मदों में आवश्यकता के दृष्टिगत औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय।

2- यह आदेश शासनादेश संख्या 183/XXVII-I/2012 दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में [www.cts.uk.gov.in](http://www.cts.uk.gov.in) से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. **संलग्नक-1** से के अन्तर्गत वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 312/XXVII(1)/2017, दिनांक 31 मार्च, 2017 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं। उक्त शासनादेश में उल्लिखित बिन्दुओं/दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए तदनुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

**संलग्नक: यथोपरि।**

भवदीय,

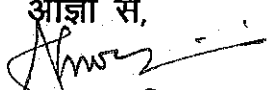
(ओम प्रकाश)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या :- 217 / XLI-1 / 17-20(प्रशि0) / 2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड ऑबेरॉय बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
- 2 आयुक्त गढवाल एवं कुमाऊँ मण्डल उत्तराखण्ड।
- 3 निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4 समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
- 5 मुख्य वित्त अधिकारी, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी-नैनीताल।
- 6 वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग-5 / नियोजन अनुभाग उत्तराखण्ड शासन।
- ✓ 7 राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर देहरादून
- 8 बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(अनूप कुमार मिश्रा)  
अनु सचिव।